(3) मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई० सी० डी० पी०—मोटे अनाज), एवं

(4) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन० पी० डी० पी०)।

इन योजनाओं के माध्यम से, धान एवं मोटे अनाजों के संकरों सहित बीजों की स्थान-विशेष अधिक उपज देने वाली किस्में, उन्नत फार्म उपकरणों, शिकलर सिंचाई सेटों के उपयोग, समेकित कृमि प्रबन्धन को अपनाने, फील्ड प्रदर्शनों के आयोजन एवं किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जा रही है।

विवरण

राज्य, जहां औसत उत्पादकता राष्ट्रीय औसत उत्पादकता स्तर से कम है, में 1995-96 में खत्म होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने हुए फसलों की औसत उत्पादकता।

(कि० ग्रा०/हैक्टेयर)

गेहूं		चावल		दलहन		मोटे अनाज	
राज्य	उत्पादकता	राज्य	उत्पादकता	राज्य	उत्पादकता	राज्य	उत्पादकता
असम	1222	अरुणाचल प्रदेश	1102	आंध्र प्रदेश	423	असम	610
बिहार	2062	असम	1345	असम	534	गुजरात	850
गुजरात	2342	बिहार	1323	गुजरात	575	हरियाणा	924
हिमाचल प्रदेश	1375	गुजरात	1466	हिमाचल प्रदेश	383	मध्य प्रदेश	788
जम्मू व कश्मीर	1446	हिमाचल प्रदेश	1314	जम्मू व कश्मीर	532	महाराष्ट्र	869
कर्नाटक	735	मध्य प्रदेश	1152	कर्नाटक	420	उड़ीसा	779
मध्य प्रदेश	1661	महाराष्ट्र	1616	महाराष्ट्र	533	राजस्थान	466
महाराष्ट्र	1379	मेघालय	1124	उड़ीसा	509		
राजस्थान	2238	मिजोरम	1536	राजस्थान	428		
सिक्किम	1201	नागालैंड	1315	तमिलनाडु	417		
उत्तर प्रदेश	2422	उड़ीसा	1413				
पश्चिम बंगाल	2324	राजस्थान	988				
		सिक्किम	1316				
		त्रिपुरा	1843				
		उत्तर प्रदेश	1875				
		पांडिचेरी	1595				
अखिल भारत	2478	अखिल भारत	1885	अखिल भारत	586	अखिल भारत	936

नोट: 10,000 टन से कम उत्पाद-, वाले राज्यों को शामिल नहीं किया गया है।

Wheat Crop hit by Weeds

2903. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the ensuing wheat crop in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh is hit by weeds and can be damaged upto 50% of the yield;

(b) the studies made by the Indian Agricultural Research Institute in this regard; and

(c) how the problem is proposed to be tackled by Government to achieve a realistic target of wheat production?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) No, Sir. State

Departments of Agriculture of Haryana, Punjab and Uttar Pradesh are not anticipating reduction in wheat production. Ensuing wheat crop in these States is having on-going major problems of *Phalaris* weed.

(b) According to studies made by the Indian Agricultural Research Institute, continuous use of isoproturon has resulted in development of resistance in *Phalaris* weed to the said weedicide in some areas of Punjab and Haryana. Based upon their investigation and research, recommendations have been made to combat the weed problem in wheat.

(c) All possible efforts being made by the Central and State Governments, Indian Council of Agricultural Research and State Agriculture Universities to tackle the *Phalaris* weed problem are as undr:—

(i) Financial assistance to farmers under a Centrally Sponsored Integrated Cereals Development Programme in wheat based cropping system as well as under the Central Sector Scheme for wheat minikit demonstration programme.

(ii) Identification of endemic pockets having *Phalaris* resistant bio-types to isoproturon and suggesting remedial measures therefor.

(iii) Popularising alternate weedicides to control *Phalaris* weed.

(iv) Ensuring availability of required weedicides.

(v) Organising joint surveys by the Experts from Central and State Government organisations to formulate appropriate strategy, to combat the menace of *Phalaris* weed.

(vi) Helping in the evaluation of newer herbicide against isoproturon resistant bio-types of *Phalaris* weed during current rabi season.

(vii) According high priority for early registration of newer herbicide under the Insecticide Act, 1968.

गुजरात में पशुपालन का विकास

2904. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में पशुपालन के विकास की बहुत अधिक संभावनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने पशुपालन के विकास तथा इस संबंध में आत्म-निर्भर बनाने के लिये गुजरात के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन विकास के लिए गुजरात राज्य सहित राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करता रहा है। योजना की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षा कार्यक्रम का विस्तार।
2. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।
3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।
4. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
5. व्यावसायिक दक्षता का विकास।
6. बूचड़खानों/पशु शव उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्त्वचन एककों के सुधार/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता।
7. प्रमुश पशुधन उत्पादों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण।
8. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।
9. राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विकास कार्यक्रम।